RNI No: UPHIN/2023/86769
www.swarajindianews.com
swarajindia2023@gmail.c swarajindi- swarajindi-

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

सांध्यकालीन समाचार पत्र

मूल्य: ₹02

स्वराज इंडिया

कानपुर,सोमवार , 08 सितंबर 2025
वर्ष: 02, अंक: 236, पृष्ठ: 8+4

सीएम योगी बोले- युवाओं को अब सिफारिश नहीं, मेहनत से मिल रही नौकरी

इनसाइड पंजाब के बाद कश्मीर में बारिश और बाढ़ से तबाही » Pg12 » Pg11

पीईटी एग्जाम: दो दिन में एक लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल

रेलवे स्टेशन पर भीड़ संभालने में जुटी रही जीआरपी-आरपीएफ

» स्टेशन से लेकर बाहर तक भीड़ का आलम, सुविधाएं हुई नाकाम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (क्ष्धअ) शनिवार और रविवार को दो पालियों में सकुशल सम्पन्न हुई। कानपुर जनपद में बनाए गए 65 परीक्षा केंद्रों पर दोनों दिनों में मिलाकर एक लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया।पहले दिन (शनिवार) लगभग 46 हज़ार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, वहीं रविवार को भी सुबह से ही हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों का केंद्रों पर आना-जाना लगातार जारी रहा। आसपास के जनपदों से आने वाले विद्यार्थियों की भीड़ ने शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दबाव बढ़ा दिया।कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की इतनी भीड़ उमड़ी कि प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन परिसर और बाहर की सड़कों तक जाम जैसी स्थिति बन गई। स्थिति को संभालने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड पर रहे। आरपीएफ की कानपुर सेंट्रल पोस्ट ने अतिरिक्त बल की तैनाती कर स्टेशन पर लगातार गश्त की। वहीं जीआरपी पुलिस द्वारा माइक से घोषणाएं कर भीड़ को सुव्यवस्थित रखने का प्रयास किया गया।परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार

टीईटी परीक्षा के फैसले से शिक्षकों में भूचाल

» दो साल में टेट करो पास वरना जबरन होगा रिटायरमेंट

» सेवा में बने रहने के लिए शिक्षकों को टीईटी पास करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ । सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने देशभर के लाखों शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब नई नियुक्ति, नौकरी में बने रहने और प्रमोशन के लिए टेट पास करना अनिवार्य है।

इस पर जहां शिक्षक समुदाय में गुस्सा है वहीं अभिभावकों ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम बताया है तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि शिक्षकों को अपडेट रहना चाहिए, बच्चों को हर वर्ष कुछ नया सिखाने के लिए पाठ्यक्रम बदलता रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शिक्षक टेट पास कर लेंगे, कुछ अगर नहीं भी कर पाएंगे तो उनकी जगह नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के लिए लागू किया गया था जिसमें राज्य सरकारों को एक वर्ष का समय दिया गया था कि वे भी इस अधिनियम को लागू करें। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई 2011 को अधिनियम को लागू किया। मगर इस पूरी प्रक्रिया में यह सवाल खड़ा होता है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुई है उन पर टीईटी का आदेश किस आधार पर लगाया जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां अधिनियम लागू होने से पहले हुई थीं उन्हें टीईटी की बाध्यता में क्यों खड़ा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2011 में आयोजित की थी तब तक टीईटी नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्तियों को प्रभावित करना व्यवहारिक नहीं प्रतीत होता। वे इसे मनमाना फैसला मानते हुए न्यायिक पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति चाहे जब हुई हो सेवा में रहने के लिए उनको टेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि शिक्षक की योग्यता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यानी अब कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे शिक्षकों को सेवा में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा।

गरीबी ने रोकी राह, पुलिस अफसर बने सहारा

शिवांक अग्निहोत्री

» गुम हुई साइकिल से परेशान थे सफाईकर्मी अनिल कुमार

» इंस्पेक्टर राज बहादुर सिंह की पहल ने दिलाया राहत और मुस्कान

कानपुर।थाना रेलबाजार में तैनात सफाईकर्मी अनिल कुमार पिछले कई दिनों से आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। उनकी रोज़ाना काम पर आने-जाने का सहारा बनी साइकिल कुछ समय पहले गुम हो गई थी। नयी साइकिल खरीदने की सामर्थ्य न होने के कारण उन्हें आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। यह जानकारी जब थाना प्रभारी निरीक्षक राज बहादुर सिंह तक पहुँची तो उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अनिल कुमार की मदद के लिए खुद पहल की।

थाना प्रभारी ने अपनी ओर से नई साइकिल दिलाकर सफाईकर्मी का बोझ हल्का किया। नई साइकिल पाकर अनिल कुमार भावुक हो गए और प्रसन्नता के साथ थाना प्रभारी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम उनके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है क्योंकि साइकिल उनके रोजमर्रा के जीवन का जरूरी साधन है।स्थानीय लोगों ने भी इंस्पेक्टर राज बहादुर सिंह की इस पहल की सराहना की और कहा कि पुलिस सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई ही नहीं करती, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी आगे आती है। इस मानवीय संवेदनशीलता ने पुलिस की सकारात्मक छवि को और मजबूत किया है।इस घटना से यह संदेश गया कि यदि अधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तो समाज में आपसी विश्वास और सामंजस्य की भावना और मजबूत हो सकती है।

गंगा का जलस्तर फिर चेतावनी बिंदु के करीब, प्रशासन सतर्क

» शुक्लागंज में दूसरी बार 113 मीटर तक पहुंचा जलस्तर

» घाटों और खेतों में घुसा पानी, विभागों में हड़कंप

प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर/शुक्लागंज। देशभर के कई राज्यों में हो रही तेज बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर दिखने लगा है। कानपुर के शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर दूसरी बार चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है।अगस्त में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 113 मीटर को पार कर 113.12 मीटर तक पहुंचा था। अब फिर तेजी से पानी बढ़ रहा है। शुक्रवार को जलस्तर 112.83 मीटर था, जबकि रविवार तक यह 113.04 मीटर पर पहुंच गया। तेजी से बढ़ते जलस्तर ने खतरे की आशंका को और गहरा कर दिया है। शहर के कई घाटों पर स्थिति बिगड़ने लगी है। अटल घाट, परमट, भैरोघाट, सरसैया घाट और भगवतदास घाट तक गंगा का पानी सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। वहीं, खेतों और रास्तों में भी पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। घाटों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर राहत कार्य शुरू किए जाएंगे।

गंगा का जल स्तर

अपस्ट्रीम- 114.73 मीटर
डाउन स्ट्रीम- 114.27 मीटर
शुक्लागंज- 113.04 मीटर
चेतावनी बिंदु- 113 मीटर
खतरे का निशान- 114 मीटर
नरोरा बांध से छोड़ा गया गंगा का जल- 1,91,442 क्यूसेक
गंगा बैराज से शुक्लागंज की तरफ छोड़ा गया गंगा का जल- 4,16,038 क्यूसेक

उत्तर प्रदेश बनेगा आईटी और एआई का वैश्विक हब

» 2047 तक डेकाकॉर्न कंपनियों का लक्ष्य

» लखनऊ और कानपुर में विकसित होंगी एआई सिटी

प्रमुख संवाददाता/ स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का वैश्विक हब बनाने की तैयारी तेज कर दी है। लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश में 15 से 20 डेकाकॉर्न कंपनियां यानी 10 अरब डॉलर वैल्यू वाली कंपनियां स्थापित हो सकें। इसके लिए सरकार ने डीप टेक्नोलॉजी, आईटी और एआई सेक्टर में निवेश बढ़ाने की रणनीति बनाई है। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से चार करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का रोडमैप तैयार किया गया है। यह कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा बल्कि प्रदेश को तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

एआई सिटी और स्टार्टअप पर फोकस

सरकार ने वर्ष 2030 तक लखनऊ और कानपुर में एआई सिटी विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा एनसीआर, लखनऊ और नोएडा को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का हब बनाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। सरकार चाहती है कि वर्ष 2030 तक कम से कम 20 यूनिकॉर्न स्टार्टअप तैयार हों। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति में सॉफ्टवेयर निर्यात बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है, जबकि स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी सरकार का खास फोकस रहेगा। इन योजनाओं के जरिए उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में तकनीकी क्षेत्र का सबसे बड़ा हब बनकर उभर सकता है।

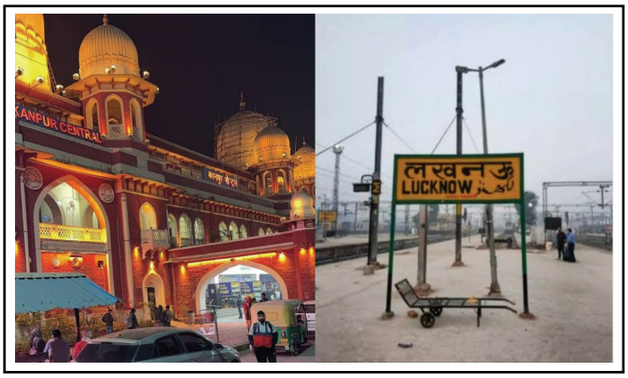

भांजे के साथ इश्क में पति का क़त्ल

» कानपुर में खौफनाक हत्याकांड की वारदात आई सामने

» कुत्तों ने खोद कर निकाल दी हड्डियां तो खुला जघन्य हत्याकांड

पत्नी और भांजे ने साजिश रचकर पति की हत्या की और शव को पास के बगीचे में गाड़ दिया

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सचेंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव से सामने आया है। यहां पत्नी ने अपने ही भांजे के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। खतरनाक साजिश के तहत पहले नींद की दवा देकर पति को बेहोश किया गया और फिर लोहे की सरिया से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद आरोपी पत्नी और भांजे ने शव को घर के पीछे बाग में दफनाया और जल्दी गलाने के लिए 10-12 किलो नमक भी डाल दिया।

मूलरूप से बांदा की रहने वाली सावित्री अपने बेटे शिववीर सिंह, बहू और तीन बच्चों के साथ सचेंडी में किराये के मकान में रहती थीं। नवंबर 2024 में वह मायके गई थीं और 5 नवंबर को लौटने पर बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। बहू ने बहाना बनाया कि वह नौकरी के लिए गुजरात गए हैं। लेकिन महीनों तक बेटे से संपर्क न होने पर सावित्री का शक गहराता गया और उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

कबूलनामे से उजागर हुई दास्तान

पुलिस की जांच में चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। बहू और उसके भांजे के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। पूछताछ में पुलिस की सख्ती के आगे भांजे ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि 2 नवंबर की रात मामा को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया और फिर सरिया से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।

कुत्तों ने उखाड़ दी साजिश की परत

हत्या के बाद शव को बाग में गाड़कर नमक डाल दिया गया। कुछ माह बाद कुत्तों ने गड्ढा खोदना शुरू किया तो हड्डियां बाहर निकल आईं और पूरा राज खुल गया।

घबराए आरोपी हड्डियां उठाकर पनकी नहर में फेंक आए, लेकिन तब तक गुत्थी सुलझ चुकी थी। यह घटना सिर्फ खून से नहीं, रिश्तों की पवित्रता को भी कलंकित करने वाली है। पत्नी और भांजे की यह खौफनाक साजिश अब पुलिस की गिरफ्त में है।

डंडों से मुर्गों का कत्ले आम, दो दबंग भाई सलाखों के पीछे

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। गोहलियापुर गांव में दुश्मनी के जुनून ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दबंगों ने आधी रात मुर्गी फार्म पर धावा बोलकर सैकड़ों बेजुबान मुर्गों को डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज़ वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी फरार हमलावरों की तलाश जारी है।

जानकारी के मुताबिक बिल्हौर थाना क्षेत्र के गोहलियापुर गांव निवासी संजय कटियार का बाग के पास मुर्गी फार्म है। संजय का कहना है कि गांव का जमील और उसके बेटे पुरानी रंजिश को लेकर लगातार

उसे धमकाते रहते थे।आरोप है शुक्रवार देर रात जमील अपने बेटे सलमान, करीम उर्फ बबलू और तीन अन्य साथियों के साथ फार्म में घुस आए। उस समय संजय वहां नहीं था। दबंगों ने मौके का फायदा उठाकर फार्म पर तांडव मचा दिया। करीब 400 मुर्गे मौके पर ढेर हो गए और कई दर्जन जख्मी पाए गए।

वारदात की भनक लगते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दबिशें शुरू कीं। रविवार को सलमान और करीम उर्फ बबलू पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन्हें कानपुर जेल भेज दिया गया।

गांव में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस सक्रिय है। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज का कहना है कि फरार आरोपितों की तलाश तेज कर दी गई है।

जल्द वह भी गिरफ्तार होंगे।और अन्य कई बिंदुओं पर जाँच की जा रही है।

मन्हापुर गांव स्कूल का मर्जर हुआ रद्द

» स्कूल पहुंच कर चहक उठे बच्चे, ग्रामवासियों ने जाहिर की खुशी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों के मर्जर (विलय) को लेकर उठे विरोध के बीच एक राहतभरी खबर सामने आई है। खराब रास्तों, एक किमी से अधिक दूरी और संसाधनों की कमी जैसे कारणों की वजह से जिले के कई सरकारी स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। सरवनखेड़ा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय मन्हापुर का युग्मन जुलाई में प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में किया गया था। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में उस समय जोर शोर से विरोध किया था कई समाचार पत्रों ने उक्त प्रकरण को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। ग्रामवासियों के संघर्ष के चलते प्राथमिक विद्यालय मन्हापुर का मर्जर निरस्त कर दिया गया है। ग्रामवासी रघुनाथ का कहना है कि हम विद्यालय स्टाफ और प्रशासन के आभारी हैं जिन्होंने हमारे बच्चों का स्कूल वापस कर दिया। ग्रामवासी विपिन का कहना है कि हमारे गांव का विद्यालय हमारी शान है विद्यालय बंद हो जाने से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। ग्रामीण बलवान का कहना है कि हम लोगों ने 2006 में बहुत संघर्ष कर विद्यालय गांव में खुलवाया था। विद्यालय का दूसरे गांव के विद्यालय में मर्ज हो जाने से हम सभी ग्रामवासियों को बहुत दुःख हुआ था लेकिन अब विद्यालय पुनः गांव में संचालित होने पर बहुत खुशी हो रही है। ग्रामवासी फूलमती का कहना है कि हमारा घर विद्यालय की बाउंड्री से सटा हुआ है विद्यालय बंद होने से एकदम सन्नाटा हो गया था बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि विद्यालय में एक बार फिर से रौनक वापस आ गई है। ग्रामीण अजय का कहना है कि बिना विद्यालय के हमारा गांव सूना हो गया था। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सारिका दीक्षित ने बताया कि विभागीय दिशा निर्देशों के तहत विद्यालय का संचालन प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में कराया जा रहा था। बच्चों को नारायणपुर पहुंचने में अत्यधिक दिक्कत हो रही थी। गांव वालों की समस्या से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया था जिस क्रम में विद्यालय का युग्मन निरस्त कर पुनः प्राथमिक विद्यालय मन्हापुर को संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए तत्क्रम में विद्यालय संचालक प्राथमिक विद्यालय मन्हापुर में किया जा रहा है। इस मौके पर शिक्षक संकुल रविंद्र द्विवेदी, निरुपम कुमार तिवारी, गोरेंद्र सचान, शिक्षक संकुल महेंद्र कटियार व विद्यालय के पूर्व सहायक अध्यापक अभिषेक द्विवेदी, शिक्षामित्र अंशो देवी ग्रामवासी अनुज, अजय, मनोज, भूरा सिंह, विपिन, बलवान, रघुनाथ, मीरा, कुलदीप, राघवेंद्र, रानी, रजौली सिंह, धनपति आदि लोग उपस्थित रहे।

जनहित कार्यों के लिए संजीव दीक्षित को मिला श्री सिद्धि विनायक सम्मान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।अपनी शालीन कार्यशैली और जनहित कार्यों के लिए जाने जाने वाले संजीव दीक्षित को श्री सिद्धि विनायक सम्मान से शहर के गणमान्य नागरिकों ने सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें श्री सिद्धिविनायक गणेश परिवार समिति के तत्वावधान में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया।कार्यक्रम में दीक्षित को पगड़ी, दुपट्टा, फूलमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित नागरिकों ने उनकी सेवाभावना, स्वच्छ छवि और आमजन की मदद के प्रति समर्पण की सराहना की।संजीव दीक्षित न सिर्फ जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करते हैं, बल्कि सेव एनीमल एंड बर्ड्स जैसी सामाजिक मुहिम भी चला रहे हैं। उनकी इस पहल की व्यापक सराहना हो रही है।कार्यक्रम में संतोष गुप्ता, बऊअन ठाकुर, ननकू गुप्ता, विशाल शुक्ला, आकाश यादव, सुशील बऊआ, बबलू जायसवाल, सतीन्द्र बाजपेई, मनोज बाजपेई, शैल शुक्ला, अनुराग साहू, संजय उपाध्याय समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

माती रोड पर शेरू कंस्ट्रक्शन ऑफिस का भव्य उद्घाटन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। नगर पंचायत अकबरपुर के माती रोड स्थित शेरू कंस्ट्रक्शन ऑफिस का भव्य उद्घाटन सदर विधायक एवं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला तथा पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने किया।इस अवसर पर सभासद बबलू भारती, इश्तियाक अहमद और हाजी अबरार ने मुख्य अतिथियों को प्रतीक चिन्ह, माला और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में डॉ. आलोक सचान, सभासद बबलू भारती, शिव सिंह नायक, समीम खान, आदेश यादव, हसीब कुरैशी, प्रमोद सिंह, जिला अध्यक्ष भूरा पाल, अमित राजपूत, सन्नी गुप्ता, कुर्बान कुरैशी, इरशाद बाबा, गुड्डू मिश्रा, मनी गुप्ता, उमेश कमल, रमेश नायक, रामपाल नायक, हिदायत उल्ला, हरमोहन यादव, बउआ राजपूत, रहमत अली, सुरेंद्र सिंह नायक, पप्पू नायक और विजय दुबेदी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

नियामक एजेंसियों की सख्ती से ही अंकुश

विभिन्न देशों द्वारा आतंकवादियों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष व परोक्ष मदद पर नजर रखने वाली वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण निगरानी संस्था यानी एफएटीएफ की हालिया रिपोर्ट चौंकाने वाली है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज बात उजागर हुई है कि आतंकवादी वित्तीय संसाधन जुटाने व खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिये बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट खुलासा करती है कि वर्ष 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में विस्फोटक पदार्थ का एक भाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था। निश्चित रूप से जिस तेजी से आतंक का नेटवर्क ऑनलाइन बाजार का फायदा उठा रहा है, वह कानून की नियामक एजेंसियों के लिये चिंता का विषय होना चाहिए। बताया जा रहा है कि आतंकवादी इंटरनेट के जरिये विस्फोटक बनाने की तरकीब भी सीख रहे हैं। इंटरनेट से बम बनाने की तकनीक सीखने की खबरों के बीच हमारे नीति-नियंताओं को इस पर अंकुश लगाने की दिशा में गंभीर पहल करनी चाहिए। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर दबाव बनाना चाहिए कि वे आतंकवादियों के लिए मददगार सामान पर सख्ती से अंकुश लगाएं। इससे पहले एफएटीएफ ने संकेत दिए थे कि पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान आतंकवादियों को न केवल पैसा व हथियार दे रहे हैं बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देने में भी मदद की जा रही है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिये आतंकवादी ऑनलाइन सेवाओं के जरिये हथियार, रसायन और थ्री डी-प्रिंटिंग सामग्री भी खरीद रहे हैं। यह विडंबना ही है कि आम नागरिकों के जीवन को सरल-सुविधाजनक बनाने के लिये जिन ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत हुई थी, वह अब आतंकवादियों की मदद का साधन बन गई है। विश्व के आतंकवादी संगठन आधुनिक तकनीक के जरिये न केवल अपने मंसूबों को पूरा कर रहे हैं बल्कि पुलिस व कानून से बचने में इंटरनेट उनका मददगार बन गया है। जिसमें आतंक की पाठशाला चलाने वाली सरकारें भी सहायक बनी हैं।विगत के कुछ वर्षों में हुए कुछ बड़े हमलों की जांच में प्रमाणिक रूप से इस बात का खुलासा हुआ है कि अब आतंकी हमलों के लिये खतरनाक ढंग से ऑनलाइन सेवाओं का दुरुपयोग किया गया है। यह विडंबना ही है कि अपराधी व आतंकवादी खुफिया एजेंसियों द्वारा अपराध नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियानों को धता बताकर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने लगे हैं। जिन ऑनलाइन सेवाओं से उपभोक्ताओं की सुविधाओं को विस्तार दिया जा रहा था, उस व्यवस्था के छिद्रों से अपराधियों ने अपनी सुगम राह तलाश ली है। जिस पर सख्त निगाह रखना सरकारों का प्राथमिक दायित्व बनता है। यदि समय रहते इस दिशा में सख्त कदम न उठाये गए तो यह व्यवस्था आतंकवादियों के खतरनाक अभियानों के लिये सुरक्षित रास्ता बन जाएगा। इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री ने हालिया विदेश यात्रा के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से किया। लेकिन पाकिस्तान जैसे कई देश आतंकवाद के विरुद्ध जारी मुहिम को कमजोर करने के प्रयास में जुटे हैं। विडंबना यह है कि पाक खुद को आतंकवाद से पीड़ित दर्शाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। यही वजह है कि गत माह वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ ने स्पष्ट किया था कि पहलगाम हमला संस्थागत बगैर वित्तीय मदद के संभव नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से एफएटीएफ के इस खुलासे से पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हुआ है।

समग्र प्रयासों में निहित जल संकट का समाधान

सोमेश गोयल

डे ज़ीरो जैसे गंभीर जल संकट की आशंका से निपटने के लिए नागरिकों को तार्किक उपयोग के जरिये जल की बचत करनी चाहिये। वहीं कृषि क्षेत्र में कम खपत वाले वैकल्पिक उपाय जरूरी हैं। जल प्रबंधन के तकनीकी नवाचार अपनाने की जरूरत है। वहीं जोर जलस्रोत संरक्षण, वर्षा जल संचयन व रिचार्जिंग पर हो।डे ज़ीरो–एक ऐसा शब्द है जो अब केवल एक संभावित आपदा नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का प्रतीक बन चुका है। यह शब्द पहली बार 2018 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में तब आया जब दक्षिण अफ्रीका का कैपटाउन शहर पानी की आपूर्ति पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। 'डे ज़ीरो' वह दिन होता है जब शहर के सभी नल बंद कर दिए जाते हैं, और नागरिकों को सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होकर सीमित मात्रा में पानी प्राप्त करना पड़ता है।

कैपटाउन में यह सीमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर निर्धारित की गई थी। हालांकि इस संकट का कारण केवल जलवायु परिवर्तन या वर्षा की अनिश्चितता नहीं था—यह दशकों की नीति विफलता, शहरों का अति-विस्तार, परंपरागत जल स्रोतों की उपेक्षा और जल प्रबंधन में बड़ी खामियों का संयुक्त परिणाम था।

कैपटाउन ने कड़ी नीतियों और नागरिक सहभागिता से इस आपदा को कुछ समय के लिए टाल दिया है। लेकिन पानी की गंभीर किल्लत की आहट अब भारत के दरवाज़े तक होने लगी है। भारत जैसे देशों में, जहां जनसंख्या अत्यधिक है, शहरीकरण अनियंत्रित है, और भूजल दोहन पर कोई स्पष्ट नियंत्रण नहीं—डे ज़ीरो अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि एक आसन्न यथार्थ है।बेंगलुरु, जिसे कभी 'झीलों का शहर' कहा जाता था, आज जल संकट के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है। यहां की अधिकांश झीलें अब या तो कचरा डंपिंग साइट बन चुकी हैं या अवैध निर्माण की भेंट चढ़ गईं। भूजल स्तर हर वर्ष 10-12 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। बेंगलुरु में डे ज़ीरो की आंशिक झलक तब देखने को मिली जब पूरे शहर में टैंकर के पानी पर निर्भरता बढ़ी।चेन्नई भी 2019 में डे ज़ीरो जैसे संकट का सामना कर चुका है जब उसके चारों जलाशय सूख गए थे। वहीं दिल्ली की स्थिति भी बेहतर नहीं—शहर की मुख्य जलधारा यमुना प्रदूषण और अतिक्रमण की शिकार है, जबकि भूजल स्तर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में जा चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों में जलापूर्ति पूरी तरह समाप्त हो सकती है।पानी के मामले में हरियाणा की स्थिति भी चिंताजनक है। धान, गन्ने जैसी अत्यधिक जल-खपत वाली फसलों का विस्तार, सिंचाई तकनीकों का अल्प उपयोग और नगण्य वर्षा जल संचयन ने भूजल अंधाधुंध तरीके से समाप्त कर दिया। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार हरियाणा के 85 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में भूजल स्तर खतरनाक स्तर पार कर चुका है।भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार केवल वर्षा की अनियमितता नहीं है, बल्कि जल निकायों पर अतिक्रमण, नीति असंगति, शहरी अपशिष्ट का जल स्रोतों में मिलना और लोगों में जल बचत के प्रति उदासीनता जैसे कारक भी उतने ही उत्तरदायी हैं।

जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कागज़ी आंकड़ों तक ही सीमित रह गया। मसलन, जल जीवन मिशन को सिर्फ 'हर घर नल' तक सीमित समझा गया, जबकि उसका मूल उद्देश्य स्थानीय जल स्रोतों का सशक्तीकरण और सामुदायिक सहभागिता के ज़रिए जल आत्मनिर्भरता था।इस स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। जल को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर नागरिक सहभागिता पर बल देना होगा। जल संरक्षण को जीवनशैली में लाना होगा – जैसे कैपटाउन में लोगों ने बर्तनों में नहाने का पानी जमा कर पौधों को सींचा, हाथ धोते समय नल बंद करना सीखा और शौचालयों में रिसाइकल पानी का प्रयोग शुरू किया।

किसानों को विवशता की हद से मुक्त कराएं

हरित क्रांति

पंकज चतुर्वेदी

बरसों पहले एक फिल्म आयी थी 'मदर इंडिया' इसमें नायिका को अम्बादास की तरह ही हल खींचते हुए दिखाया गया था। बचपन में देखी फिल्म का वह दृश्य आज भी आंखों में आंसू ला देता है। उम्मीद ही की जा सकती है कि उस फिल्म की यह पुनरावृत्ति-अम्बादास का हल जोतना-कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी का भाव जगायेगी।हाल ही में सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो वायरल हुआ था। आपने भी देखा होगा एक बूढ़ा किसान बैल बनकर अपने खेत को जोत रहा है। उसे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है इस काम में, इसका अहसास उसके चेहरे को देखकर अनायास ही हो जाता है। उसके पीछे से टेका देने का काम उसकी बूढ़ी पत्नी कर रही है। यह चित्र लगभग 70 वर्षीय किसान अम्बादास पवार और उसकी पत्नी का है। चार बीघा जमीन है दोनों के पास। पर हल चलाने के लिए बैल खरीदना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वह खुद बैल बन गया है!

ज्ञातव्य है कि यह दृश्य उस महाराष्ट्र का है जिसकी गणना देश के विकसित राज्यों में होती है। ज्ञातव्य यह भी है कि देश में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं में महाराष्ट्र के किसानों की संख्या सर्वाधिक है- पिछले तीन महीनों में अर्थात? अप्रैल, मई, जून, 2025 में महाराष्ट्र में 767 किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है! पिछले दस सालों में यह आंकड़ा औसतन प्रतिदिन दस आत्महत्याओं का पड़ता है। पचपन साल पहले देश में हरित क्रांति हुई थी। यह एक सच्चाई है। कृषि क्षेत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिकों और हमारे किसानों ने 1970 में इस सच्चाई को साकार किया था। लेकिन यह सच्चाई जितनी मीठी है, उतनी ही कड़वी यह सच्चाई भी है कि हरित क्रांति के बावजूद हमारे किसानों की हताशा के फलस्वरूप देश में होने वाली आत्महत्याओं की संख्या लगातार डरावनी बनी हुई है। किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का यह शर्मनाक सिलसिला हरित क्रांति के चार-पांच साल बाद ही शुरू हो गया था!

इसका कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह एक खुला रहस्य है कि कृषि क्षेत्र में विकास के सारे दावों के बावजूद अधिसंख्य किसान अभावों की जिंदगी ही जी रहे हैं। इस दौरान बड़े-बड़े दावे हुए हैं किसानों के विकास के। करोड़ों-करोड़ों रुपया कथित 'खुशहाल किसानों' की तस्वीर दिखाते विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है; हर किसान का बैंक खाता होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि विज्ञापनों की सच्चाई और स्थिति की भयावहता कुछ और ही वर्णन कर रही है। यदि हमारा अन्नदाता सचमुच समृद्ध होता जा रहा है तो फिर देश की अस्सी करोड़ आबादी मुफ्त अनाज लेने के लिए विवश क्यों है? इस मुफ्त अनाज को भले ही कुछ भी नाम दिया जाये, पर हकीकत यही है कि सरकार के सारे दावों और वादों के बावजूद देश का औसत किसान आज भी ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीता है और ऋण में ही मरने के लिए शापित है। यह शाप कब दूर होगा?किसानों की दुर्दशा के जो कारण बताये जाते हैं, उनमें सबसे पहला स्थान ऋण का ही है। साहूकारों से, बैंकों से और अन्य सरकारी एजेंसियों से हमारा किसान ऋण लेता है। और यह ऋण समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता! जिन्हें ऋण मिल जाता है, उनकी जिंदगी उसे चुकाने में ही कट जाती है। यहीं इस बात को भी रेखांकित किया जाना ज़रूरी है कि भारत का किसान उन उद्योगपतियों की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार है जो बैंकों से अरबों का ऋण लेते हैं और या तो स्वयं को दिवालिया घोषित कर देते हैं या फिर विदेश में कहीं ऐसी जगह पर बस जाते हैं जहां से उन्हें भारत प्रत्यर्पित करना आसान नहीं होता। अरबों-खरबों के इन देनदारों को इस बात से भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें बेईमान कह रही है। उनकी तुलना में हमारा किसान कहीं अधिक शर्मदार है।

अनवरगंज नगरीय स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, 8 गैरहाजिर

» डीएम ने कहा कि लापरवाहों पर होगी कार्रवाई

» स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए डीएम का सख्त रुख

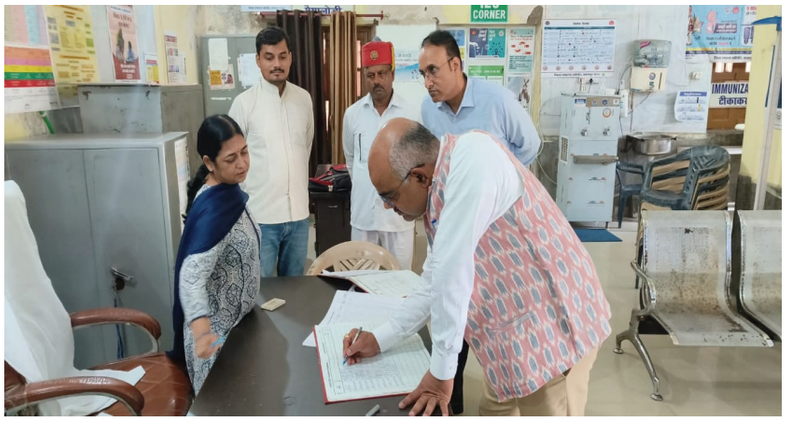

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार सुबह 9:30 बजे नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, अनवरगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में पाई गई खामियों पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए आठ गैरहाजिर स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गैरहाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई

उपस्थिति पंजिका की जांच में एक स्थायी और सात संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले। डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने तथा संविदा कार्मिकों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। साथ ही, संबद्धिकरण को लेकर भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।

लैब और दवाओं की व्यवस्था की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लैब की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। जब पता चला कि सितंबर माह में अब तक केवल 14 जांचें हुई हैं, तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और जांच संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं, दवाओं की उपलब्धता की जांच कर मरीजों को निर्बाध रूप से दवा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध कराना ही प्रशासन की प्राथमिकता है। नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई से सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

अखिलेश से मुलाकात कर सपाइयों ने सुनाई बिल्हौर की समस्याएँ

पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात कर समस्याएं बताते सपाई

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ जाते समय आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अरौल रेस्ट एरिया स्थित एक होटल के बाहर सपाइयों से मिले। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी की पूर्व विधान सभा प्रत्याशी रचना सिंह गौतम और उनके पति पंकज यादव ने बिल्हौर की कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कोठी गंगा घाट को पुनः चालू करने, पुलिस उत्पीड़न, और फर्जी मुकदमों जैसी समस्याएँ उठाईं। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से देखा जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। रचना सिंह गौतम ने मुलाकात को सकारात्मक बताया और कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने क्षेत्र के हित के लिए त्वरित समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान शशिकांत पाल,बबलू, लोकेश अवस्थी, ऋषभ यादव, सपा नेत्री कंचन पाल,बिलाल समेत कई अन्य सपाई भी मौजूद रहे।

सुबह का सूरज चढ़े न चढ़े, अंगूर की बेटी ज़रूर चढ़ जाती है!

» स्टेशन के सामने देशी शराब की दुकान पर ठेकेदार ने नियमों को दिखाया ठेंगा

» सुबह से ही बिकने लगती है दारू, खुलेआम पैग लगाते हैं शराबी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कस्बे के स्टेशन के सामने शराब का ठेका सुबह-सुबह ही गुलज़ार हो जाता है। तय समय को ठेंगा दिखाते हुए ठेकेदार-संचालक कुण्डी खटखट करो और बोतल उठाओ की नीति पर काम कर रहे हैं। सुबह होते ही अंगूर की बेटी के दीवाने मजदूर और राहगीर बोतल थामे ठेके से निकलते नज़र आते हैं।

कोई वहीं पैग लगाता है, तो कोई स्टेशन और बस स्टॉप के किनारे झूमता-लड़खड़ाता दिखता है। माहौल ऐसा होता है मानो सुबह की खुमारी, प्रशासन पर भारी। सबसे बड़ी चिंता यह है कि स्टेशन के ठीक सामने और पास ही बने स्थायी बस स्टॉप से रोज़ाना सैकड़ों बच्चे और छात्र ट्रेन और बस, ऑटो पकड़कर पढ़ाई के लिए शहर व आसपास के कॉलेज जाते हैं।

लोगों का कहना है कि बच्चों को नशे में धुत लोगों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे न केवल सुरक्षा खतरे में पड़ती है बल्कि माहौल भी बिगड़ रहा है।स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सुबह शराब बिक्री से बाज़ार का माहौल भी प्रभावित होता है।

दुकानदारी पर असर पड़ता है और आए दिन शराबियों की हरकतों से विवाद खड़े हो जाते हैं। राहगीरों के लिए गाली-गलौज और झगड़े आम नज़ारा बन गए हैं।

इन पर कार्रवाई न होने से शराब माफिया और ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं।

सवाल है कि आखिर किसकी शह पर नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और कब तक स्टेशन और बस स्टॉप जैसे संवेदनशील इलाकों को नशे का अड्डा बनने दिया जाएगा?

सुबह-सुबह कुण्डी खटाकर शराब लेता ग्राहक, नियमों को ठेंगा दिखाता ठेकेदार

काकादेव पुलिस ने रोका तलाक और न्यायिक जटिलताओं का संकट

प्रमुख संवाददाता / स्वराज इंडिया

कानपुर। थाना काकादेव में आज दिनांक 8/9/25 को श्रीमती शिल्पी कौशल ने पति अनूप कौशल के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि पति आए दिन शराब पीकर मारपीट करते हैं

और घर वालों के समझाने पर आत्महत्या करने की धमकी देते हैं। कल तो उन्होंने गैस सिलेंडर खोलकर पूरे घर में गैस भर देने जैसी खतरनाक हरकत की, जिससे परिवार और पड़ोसी भयभीत हो गए।सूचना मिलते ही थाना काकादेव की पुलिस टीम सक्रिय हुई।

» शराब और आत्महत्या की धमकी के बाद दंपति का थाने में कराया सुलह

» पुरानी झगड़ों को भूलकर परिवार के लिए किया समझौते का प्रयास

वरिष्ठ उप निरीक्षक शिवकरण वर्मा और काउंसलर श्रीमती शगुन खट्टर के मार्गदर्शन में पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाया। इस दौरान दंपति बार-बार अपनी पुरानी शिकायतों और झगड़ों को लेकर रो-रो कर न्यायालय में संबंध विच्छेद का मुकदमा दायर करने को तैयार थे।शादी वर्ष 2011 में हुई थी और दंपत्ति की एक पुत्री भी है। पुलिस और काउंसलर की लगातार समझाइश के बाद दोनों पक्ष पुराने विवादों को भूलकर एक साथ रहने के लिए तैयार हुए। अधिकारियों ने दोनों परिवारों को यह समझाया कि तलाक या न्यायिक प्रक्रिया से केवल परिवार टूटेगा और बच्चों का मानसिक व सामाजिक विकास प्रभावित होगा।

इस प्रयास के बाद दंपत्ति ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहने का निर्णय लिया। इस प्रकार काकादेव पुलिस ने न केवल दंपत्ति के बीच सुलह कराई, बल्कि दोनों परिवारों को कानूनी दाव-पेच और टूटती परिवारिक संरचना से भी बचाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि ऐसे मामलों में समझौता और काउंसलिंग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

ईंट से कूचकर किसान की निर्मम हत्या

» मृतक रामशरन का शव हल्केश की दुकान पर मिला, परिजनों में मचा कोहराम

» पुलिस अधीक्षक व टीम मौके पर, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। मूसानगर थाना क्षेत्र के खिरियन पुरवा गांव में रविवार रात 35 वर्षीय किसान रामशरन की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया कि रामशरन को शेरपुर गुड़ा से पैसा लेने का कहकर घर से बाहर भेजा गया था। परंतु, वह तय समय पर वापस नहीं लौटा, जिससे परिवार के लोग चिंतित हो गए।परिवार और ग्रामीणों ने रातभर खोजबीन की, लेकिन किसी तरह का सुराग नहीं मिला। सुबह लगभग 6 बजे ग्रामीणों ने रामशरन को हल्केश पुत्र रमेश की दुकान के पास मृत अवस्था में पड़ा देखा। मौके पर पहुंचकर परिजन और गांव वाले हक्के-बक्के रह गए। मृतक का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी सीमा देवी और छोटे बच्चे दीपा व दीपराज का रो-रो कर बुरा हाल था।

घटना की सूचना मिलते ही मूसानगर थाना प्रभारी कालीचरण, क्षेत्राधिकारी संजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और आसपास के कई जगहों पर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हत्या का स्पष्ट कारण नहीं पता चला है। मृतक के पिता शिवनाथ ने मूसानगर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब स्थानीय लोगों से पूछताछ कर हत्या के संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।गांव में इस घटना के बाद शोक और भय का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भैंस चोरी के शक में गांव वालों ने नवयुवकों पर किया हमला, पुलिस के साथ भी की मारपीट

» गौरी गांव में दर्जनों युवकों को बंधक बनाकर पीटा, पुलिस वाहन में तोड़फोड़

» थाना फोर्स ने पहुंचकर नवयुवकों को छुड़ाया, दर्ज हुआ मारपीट का मुकदमा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।देवराहट थाना क्षेत्र के गौरी गांव में भैंस चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने लगभग एक दर्जन नवयुवकों को पकड़कर बेरहमी से पीटा और उन्हें बंधक बना लिया।

घटना की सूचना पर 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गांव वालों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया और सरकारी जीप में तोड़फोड़ की।जानकारी के अनुसार, पनिया मऊ गांव के कुछ लोग लोडर में घूमते युवकों को देखकर उन्हें भैंस चोर समझ बैठे। उन्होंने अन्य गांववालों को बुलाया और करीब 50-60 लोग इकट्ठा होकर नवयुवकों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। कई युवक गंभीर रूप से घायल हुए। इस दौरान पुलिस के साथ भी मारपीट हुई, और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया गया।

देवराहट थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और नवयुवकों को छुड़ाया। घायल प्रतीक, अजय, राजकुमार, कपिल, आदर्श, विशाल और अमन को सरकारी अस्पताल पुखरायां में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल राजकुमार को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने कुंवर सिंह, सत्येंद्र, अंकित और नवनीत के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रनियां-बिलई मार्ग पर विभागीय लापरवाही से ठप चौड़ीकरण कार्य

» 10 महीने पहले जारी हुआ था टेंडर, अब तक नहीं शुरू हुआ निर्माण

» बरसात में गड्ढों से गुजर रहे राहगीर, खतरे के साए में सफर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की लापरवाही ने रनियां-बिलई संपर्क मार्ग पर सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के करीब 10 महीने बाद भी सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं हो सका। नतीजा यह है कि इन दिनों बारिश में सड़क जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और

राहगीरों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, रनियां से प्रसिद्धपुर, पतारी, गदनापुर होते हुए बिलई गांव तक साढ़े 5 किलोमीटर लंबे मार्ग को चौड़ा करने के लिए शासन से ?7 करोड़ 17 लाख 79 हजार का टेंडर जारी हुआ था। नवंबर 2025 तक कार्य पूरा होना था। बीते 14 नवंबर को मिट्टी भराई शुरू भी हुई, लेकिन उसके बाद काम ठप हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उम्मीद थी सड़क जल्द ही बन जाएगी और सफर सुगम होगा, लेकिन विभागीय लापरवाही से अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।

इस बाबत पूछे जाने पर जेई लोकेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि एक साथ पांच सड़कों का टेंडर जारी किया गया था। बाकी जगह काम चल रहा है और उम्मीद है कि 20 सितंबर से रनियां-बिलई मार्ग पर भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

आईआईए कानपुर देहात की वार्षिक आम सभा हुई संपन्न

जल संरक्षण का संदेश देते हुए सात नदियों का जल एकत्र कर हुआ शुभारंभ

» उद्योगों की समस्याओं के समाधान और शिक्षा सुधार को लेकर चेयरमैन का संकल्प

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुरदेहात।इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) कानपुर देहात चैप्टर की वार्षिक आम सभा शनिवार को कानपुर स्थित एक होटल में संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कपिल भाटिया और पदाधिकारियों ने जल संरक्षण का संदेश देते हुए सात नदियों का जल एक बड़े घड़े में एकत्र कर की। इस अनूठे तरीके से सभा का शुभारंभ कर जल बचाने का संकल्प दोहराया गया।बैठक में पूर्व चेयरमैन आलोक जैन ने पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए

पिछले दस वर्षों में आईआईए की उपलब्धियां गिनाईं। वहीं नवनियुक्त चेयरमैन पियूष जैन ने अपने संबोधन में कहा कि उद्योगों और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी आईआईए का लक्ष्य है। उन्होंने ऐलान किया कि पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत अभियान के तहत जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करवाया जाएगा।राष्ट्रीय उद्देश्य एक सूर्य, एक विश्व के तहत आईआईए सदस्य हीलियम सोलर पावर कंपनी ने इकोनॉमी और कमर्शियल सेक्टर पर विशेष प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित उद्यमियों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में सुनील वैश्य, कपिल भाटिया, तरुण खेत्रपाल, विजय अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, सचिन गर्ग, रोहित बृज पुरिया, तुषार गुप्ता, अनूप गुप्ता, शालिनी गुप्ता, पुनिका गुरुटाटा, मनोज गुप्ता, विनय कनोडिया, जयेश गुप्ता, पीसी कुरेले समेत दो सौ से अधिक उद्यमी शामिल रहे।

फेरबदल

कानपुर देहात में तबादला एक्सप्रेस

एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने किया बड़ा फेरबदल

» कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कई उपनिरीक्षकों के प्रभार बदले गए

» चौकियों पर नए प्रभारी तैनात, पुलिस महकमे में मची खलबली

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने रविवार देर शाम बड़े पैमाने पर तबादले किए। तबादला एक्सप्रेस के तहत कई उपनिरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं और तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इस फेरबदल के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।

पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक सुभाष कुमार को

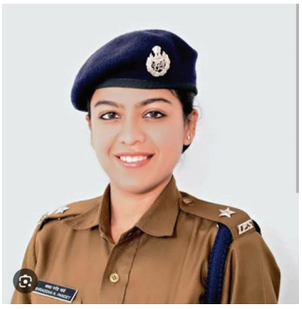

प्रभारी व्यापार प्रकोष्ठ बनाया गया है, वहीं अवनींद्र पाल को सिटीजन चार्टर सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपनिरीक्षक उमर मोहम्मद खां को मॉनिटरिंग सेल का प्रभार मिला है, जबकि रमाकांत द्विवेदी को प्रभारी सदर मालखाना नियुक्त किया गया है।इसी तरह सौरभ कुमार को चौकी प्रभारी जैनपुर (थाना अकबरपुर) भेजा गया है। सुनील सिसोदिया को चौकी प्रभारी ग्रोथ सेंटर (थाना गजनेर) की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं ललित कुमार को चौकी प्रभारी मंगटा (थाना गजनेर) बनाया गया है। रामलखन को चौकी प्रभारी रसधान (थाना सिकंदरा) का प्रभार सौंपा गया है, जबकि सुधीर अब चौकी प्रभारी बिहारघाट (थाना डेरापुर) रहेंगे। इसके अलावा प्रशांत कुमार को चौकी प्रभारी कांधी (थाना डेरापुर) नियुक्त किया गया है।

इस बड़े फेरबदल से पुलिस विभाग में नई ऊर्जा और जवाबदेही की उम्मीद जताई जा रही है।

(स्वराज इंडिया की खबर का असर)

शिकायतकर्ता की जिद से बैकफुट पर अयोध्या विकास प्राधिकरण !

» अबकी बार जांच कमेटी में शामिल होगा शिकायतकर्ता

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। स्वराज इंडिया की खबर ने एक बार फिर बड़ा धमाका कर दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के जिन सचिव साहब के कानों पर शिकायतें सुनाई ही नहीं देती थीं, वे अब बैकफुट पर आ गए हैं। वजह सिर्फ एक शिकायतकर्ता की लगातार सक्रियता और दबाव।

बता दें कि उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 04.09.2025 के तहत ग्राम मांझा बरहटा स्थित भू-खण्ड संख्या 989, 990, 991, 992, 992ख (मानचित्र मंगलम होटल एण्ड

स्वराज इंडिया www.swarajindianews.com अयोध्या कानपुर,गुरूवार 04 सितंबर, 2025 10

अयोध्या विकास प्राधिकरण: गुम होती पत्रावलियां और पल्ला झाड़ते अधिकारी

» भ्रष्टाचार के दलदल में धँसता प्राधिकरण, 'ईमानदारी' हो रही बेअसर

» प्राधिकरण का ताकतवर लेखपाल बना 'भस्मासुर'

होटल मंगलम एंड रिसॉर्ट्स का मानचित्र विवादों में , तथ्यों को छिपाने का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। पग-पग पर भ्रष्टाचार रूपी दलदल में फँसता विकास प्राधिकरणज। ईमानदारी की कलम यहाँ इतनी बौनी साबित हो रही है कि तथ्यों और न्यायालय के आदेशों को छिपाकर भी मानचित्र पास किए जा रहे हैं।सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि होटल मंगलम एंड रिसॉर्ट्स का मानचित्र गलत तथ्यों और वाद को छुपाकर पास करा लिया गया। इस पूरे प्रकरण में प्राधिकरण के कुछ अधिकारी तेजतर्रार वीसी की कार्यप्रणाली पर 'जंग' लगाने में जुटे दिखाई देते हैं।

ताकतवर लेखपाल कैसे बना है 'भस्मासुर' !

आरोप है कि प्राधिकरण अपने ही लेखपाल को बचाने के लिए एक के बाद एक गलतियां कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, ताकतवर लेखपाल से एक सप्ताह का स्पष्टीकरण तक नहीं लिया जा सका। भ्रष्टाचार छिपाने की इस जुगत में प्राधिकरण खुद सवालों के घेरे में है। सवाल यह उठता है कि

आखिर कौन सा दबाव है, जो वीसी फर्जी आख्या पर भी कार्यवाही नहीं कर पा रहे। न्यायालय के स्थगनादेश को छिपाकर पास कराए गए मानचित्र पर एक महीने से कार्रवाई अटकी हुई है। 21 अगस्त 2025 को दिए गए प्रार्थना पत्र पर खुद वीसी ने जांच का आदेश दिया था, मगर वह पत्र रहस्यमय तरीके से दबा दिया गया।

सचिव कहते हैं मेरे द्वारा नहीं रोका गया पत्र। ओएसडी का बयान फ़मुझ तक नहीं पहुँचा पत्र। प्रभारी मानचित्र और नियोजन लिपिक दोनों ही अनजान बने बैठे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर वह कौन सी गुमनाम जगह है जहाँ भ्रष्टाचार से जुड़ी पत्रावलियां बार-बार गुम हो जाती हैं। गलत शपथपत्र

और साक्ष्य सामने आने के बाद भी मानचित्र जारी होना इस बात का सबूत है कि जांच सिर्फ़ 'लुका-छुपी' का खेल है। सचिव का बयान कार्यवाही कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे पूरे प्रकरण को और संदेहास्पद बना देता है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में जल्द ही साक्ष्यों के साथ प्रेस के माध्यम से बड़ा खुलासा होगा।

रिजॉर्ट) से जुड़ी पत्रावली संख्या एएफडीए/बीपी/22-23/0413 दिनांक 13.02.2023 पर आखिरकार जांच समिति गठित कर दी गई है। शिकायतकर्ता को भी जांच समिति में शामिल किया गया है।10 सितम्बर 2025, पूर्वान्ह 11 बजे प्राधिकरण कार्यालय में होगी सुनवाई। शिकायतकर्ता को सभी जरूरी प्रपत्रों के साथ समिति के सामने पेश होना होगा। अब तक प्राधिकरण की फाइलों में धूल फांकते सत्य को जब शिकायतकर्ता ने हिलाया, तभी सचिव जी को जांच कमेटी याद आई। सवाल बड़ा है क्या यह पारदर्शिता की ओर बढ़ता कदम है या फिर सिर्फ दबाव में उठाया गया दिखावटी फैसला? सूत्रों की माने तो उक्त मामले में एडीए प्रशासन आरोपी होटल मालिक को बचाने में कोई कोर कसर नही छो? रहा है। वजह वही एडीए की पुरानी कहानी है जोकि अक्सर चर्चा में रहती है।

श्री रामजन्मभूमि ट्रस्ट में क्षत्रिय प्रतिनिधित्व की मांग

» सूर्यवंशी परंपरा का हवाला देते हुए समाज ने खोला मोर्चा

» खुले पत्र में प्रख्यात समाजसेवी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजेश सिंह मानव का सुझाया गया नाम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर नई बहस छिड़ गई है। क्षत्रिय समाज ने खुले पत्र के माध्यम से ट्रस्ट से आग्रह किया है कि प्रभु श्रीराम की परंपरा और कुल की गरिमा का सम्मान करते हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज से एक प्रतिनिधि को सदस्यता दी जाए।पत्र में कहा गया है कि हाल ही में ट्रस्ट के सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से जो रिक्तता बनी है, उसे भरने के लिए क्षत्रिय समाज से जुड़ा चेहरा होना चाहिए। समाज ने जोर देते हुए

भारत के सबसे बड़े विद्वान बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ला ब्रह्मचारी जी महाराज के दासानुदास श्री राजेश सिंह जी (मानव) संत, गौ एवं समाजसेवी संरक्षक श्री आदित्यनाथ गौ सेवा समिति एवं पूर्व अध्यक्ष स्वायत शासन कर्मचारी परिषद , निवासी -अयोध्या सदन , जनौरा अयोध्या जी

खुला पत्र

विषय : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने हेतु निवेदन।

मान्यवर,
सादर प्रणाम।

हम, संपूर्ण क्षत्रिय समाज की ओर से, इस पत्र के माध्यम से अपने गहन भाव एवं आस्था आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल ही में ट्रस्ट के माननीय सदस्य *श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी* के निधन से ट्रस्ट को क्षति पहुँची है। वर्तमान में ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय सदस्य का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि प्रभु श्रीराम स्वयं सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए थे।

यह विषय केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रद्धा, मर्यादा एवं गौरव और अर्चन पद्धति से भी गहराई से जुड़ा है कि प्रभु श्रीराम के कुल का प्रतिनिधि ट्रस्ट में सम्मिलित हो।

अतः, हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि **सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज के सम्मानित प्रतिनिधि श्री राजेश सिंह जी (मानव)** को ट्रस्ट की सदस्यता प्रदान की जाए।

प्रमुख कारण :

1. श्री राजेश सिंह जी (मानव) क्षत्रिय समाज के अग्रणी, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से सक्रिय और विद्वान प्रतिनिधि हैं। वे शास्त्रों के गहन ज्ञाता हैं और अयोध्या के सांस्कृतिक एवं शास्त्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हैं।
2. वे रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े वैचारिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलुओं में निरंतर योगदान देते रहे हैं।
3. उनका व्यक्तित्व समर्पण, धर्मनिष्ठा एवं संगठन क्षमता से परिपूर्ण है, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अत्यंत उपयुक्त है।

हमें विश्वास है कि भारत सरकार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में, श्रीराम की परंपरा और सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल की गरिमा और मर्यादा का सम्मान करते हुए इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा।

आपके अनुकूल उत्तर की प्रतीक्षा में संपूर्ण क्षत्रिय समाज । सानुरोध

कहा कि जब प्रभु श्रीराम स्वयं सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए थे, तब ट्रस्ट में क्षत्रिय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति परंपरा और आस्था दोनों के विपरीत है।

सूर्यवंशी राजेश सिंह मानव का सुझाया नाम

खुले पत्र में क्षत्रिय समाज ने अयोध्या के जाने-माने विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह मानव का नाम प्रस्तावित किया है। पत्र में तर्क दिया गया कि मानव लंबे समय से

रामजन्मभूमि आंदोलन के सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक पक्ष से जुड़े रहे हैं। शास्त्रों के गहरे जानकार होने के साथ वे संगठन क्षमता और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण हैं, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों को और मजबूती देंगे।

समाज ने साफ कहा है कि यह केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था का विषय है। यदि ट्रस्ट क्षत्रिय प्रतिनिधि को शामिल करता है तो यह श्रीराम की परंपरा और कुल की गरिमा का सम्मान होगा। अब सबकी निगाहें ट्रस्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं कि क्या वह समाज की इस ऐतिहासिक मांग को स्वीकार करेगा।

बिना पैमाइश, बिना पारदर्शिता 1.5 करोड़ का प्रस्ताव कैसे?

» अवध विश्वविद्यालय के सामने तालाब पर सौंदर्यीकरण का खेल!

» सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सावंत बोले हो रहा है कि खेल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

अयोध्या। डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सामने स्थित ऐतिहासिक तालाब का सौंदर्यीकरण अब सवालों के घेरे में है। अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने इस तालाब को संवारने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सावंत ने इसे बिना पैमाइश और बिना पारदर्शिता की कवायद करार दिया है।

सावंत का कहना है कि तालाब का मूल राजस्व रकबा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया और अतिक्रमण हटाए बिना सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भेजना जनता को गुमराह करने जैसा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना की विस्तृत डीपीआर को दबाकर रखा गया है, ताकि जनता असली तस्वीर न देख सके। सवाल यह भी उठाया कि अगर पैमाइश ही नहीं कराई गई तो प्रस्ताव कैसे बन गया?उक्त मामले में और भी चुभते सवाल अभिषेक सावंत ने खड़े किए जब लंबित आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया गया, तो यह जानकारी मीडिया तक कैसे पहुँची? क्या यह सब जल्दबाज़ी में सिर्फ दिखावे के लिए किया गया? बिना प्रेस वार्ता और आधिकारिक ब्रीफिंग के प्रस्ताव की जानकारी अखबारों तक पहुँचना किस पारदर्शिता की निशानी है? सावंत ने साफ कहा कि यह मुद्दा सिर्फ तालाब की सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि अयोध्या की धरोहर बचाने और प्रशासनिक जवाबदेही तय कराने की लड़ाई है। उन्होंने मांग की कि सबसे पहले तालाब से अतिक्रमण हटाया जाए, मूल स्वरूप बहाल किया जाए, डीपीआर और पैमाइश रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और लंबित आरटीआई का तत्काल जवाब दिया जाए। उनका कहना है इतनी बड़ी लागत से बनने वाला प्रस्ताव यदि जनता से छिपाकर, कागज़ों में घुमाकर और मीडिया में लीक कर आगे बढ़ाया जा रहा है तो यह विकास नहीं, बल्कि खेल है।

सीएम योगी बोले- युवाओं को अब सिफारिश नहीं, मेहनत से मिल रही नौकरी

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोकभवन में उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1,510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में नौजवानों को नौकरी पाने के लिए न सिफारिश की ज़रूरत है, न लेन-देन की। जिसने तैयारी की, वही चयनित हुआ है। मुख्यमंत्री ने मंच से 11 अनुदेशकों को अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपा और कहा– फ्जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो जाता है और वह अभ्यर्थियों से आंख नहीं मिला पाता। पिछली सरकारों ने यही स्थिति पैदा कर दी थी। लेकिन अब यूपी में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की गारंटी है।

यूपी में नौकरियों की बौछार, लगातार दी जा रही युवाओं को नौकरियां

सीएम के हाथों नियुक्ति पाने वाले रायबरेली की पल्लवी, उन्नाव की स्मृति दुबे, मीरजापुर की ममता वर्मा, मुजफ्फरनगर के संदीप, अयोध्या के सौरभ यादव, बस्ती की प्रियंका सिंह, देवरिया के अभिलाष सिंह व सुशील कुमार, जालौन के विवेक मिश्र, कानपुर नगर की पिंकी कुमारी और कन्नौज की ममता यादव सहित अन्य रहीं।

हर महीने पूरी हो रही है नियुक्ति प्रक्रिया

सीएम ने बताया कि बीते साढ़े आठ सालों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। हर महीने किसी न किसी आयोग या बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इसके अलावा रोजगार मेलों और स्किल डेवलपमेंट से लाखों युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर मिले हैं।

यूपी बना अब विकास का इंजन

योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी को 'बीमारू राज्य' कहा जाता था। लेकिन अब 25 करोड़ जनता, प्रतिनिधियों और डबल इंजन सरकार के प्रयास से यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज प्रदेश अधिकांश योजनाओं में देश में नंबर एक या टॉप थ्री में है।

60 लाख से अधिक को रोजगार

सीएम ने बताया कि पिछले आठ वर्षों में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। इनमें 14 लाख ने यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन से प्रशिक्षण लेकर रोजगार पाया। वहीं, MSME सेक्टर में 96 लाख यूनिट चल रही हैं, जिनमें करोड़ों को काम मिल रहा है।

मई से सितंबर तक बड़े पैमाने पर नियुक्तियां

7 सितंबर-1,510 अनुदेशक
6 सितंबर- परिवहन विभाग में महिला परिचालक
29 अगस्त -9 सहायक खेल प्रशिक्षक
28 अगस्त - रोजगार महाकुंभ में 16,897 युवाओं को जॉब
27 अगस्त-2,425 मुख्य सेविका व 13 फार्मासिस्ट
6 अगस्त-बरेली में 6,000 युवाओं को नौकरी
17 जुलाई-विश्व युवा कौशल दिवस पर 20,997 युवाओं को जॉब ऑफर
15 जून-60,244 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र

युवाओं को सीएम का संदेश

सीएम ने नवचयनित अनुदेशकों से कहा— आपकी नियुक्ति बिना सिफारिश और लेन-देन के हुई है, इसलिए अपेक्षा है कि आप भी छात्रों को ईमानदारी से गाइड करें। टाइमपास करने से कोई फायदा नहीं, ईमानदारी से किया गया प्रयास ही सफल होता है।

उत्तर प्रदेश टीबी मेल हेल्थ विजिटर्स संघ के अध्यक्ष बने सागर पाण्डेय

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश टीबी मेल हेल्थ विजिटर्स संघ का चुनाव रविवार को जिला क्षय रोग केंद्र राजेन्द्र नगर लखनऊ में सम्पन्न हुआ। चुनाव में राज्य कर्मचारी अध्यक्ष पर पर सागर पाण्डेय तथा महामंत्री अश्वनी पाण्डेय को चुना गया। इस अवसर पर सागर पाण्डेय ने कहा कि संघ के सभी नियमों का पालन किया जाएगा साथ ही विकास की रूपरेखा को और प्रभावी की जाएगी। चुनाव राज्यकर्मचारी संयुक्त परिवाद यूपी के महामंत्री आर के निगम वरिष्ठ उपाध्यक्ष आए के वर्मा तथा संप्रेक्षक नागेन्द्र भूषण पाण्डेय कि देख.रेख में सम्पन्न कराया गया। इसके पूर्व बैठक में संवर्ग की मांगों को निस्तारित किये जाने पर जोर दिया गया।

पंजाब के बाद कश्मीर में बारिश और बाढ़ से तबाही

» प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ ने बढ़ाया संकट

» किसानो को चिंता है कि उनकी बर्बाद होती फसलें और फैलती बीमारियां बन रही खतरा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर। पंजाब में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात के बाद अब जम्मू-कश्मीर भी इसकी चपेट में है। लगातार कई दिनों तक हुई मूसलधार बारिश ने यहां धान की फसल और सेब के बागानों को भारी नुकसान पहुँचाया है। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है।गुरुवार को झेलम नदी का तटबंध टूट जाने से श्रीनगर समेत तीन जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया।

अचानक आई आपदा में करीब 9,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग के सैकड़ों जवान लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं।

किसानों का कहना है कि खेतों और बागानों में पानी भरने से धान की फसल पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है। वहीं, सेब के बागानों में पेड़ उखड़ने और स्कैब जैसी द्वितीयक बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। अगर पानी जल्द नहीं निकला तो पूरी साल की मेहनत चौपट हो जाएगी, एक किसान ने कहा।

प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ बना संकट की जड़

विशेषज्ञों का मानना है कि हर साल कश्मीर घाटी में बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं के पीछे केवल मौसम को दोष नहीं दिया जा सकता। पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, अवैध खनन, नदियों के किनारे अनियंत्रित निर्माण और जंगलों के सिकुड़ते दायरे ने जलवायु संतुलन बिगाड़ दिया है।पहाड़ों पर पेड़ों की जड़ों के कटने से मिट्टी का क्षरण तेजी से हो रहा है, जिसके चलते तेज बारिश में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और तटबंध टूट जाते हैं।

विशेषज्ञों की चेतावनी, नहीं सुधरे तो और खराब होंगे हालत

पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर समय रहते कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों में वन और जलस्रोतों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में और भी विनाशकारी बाढ़ देखने को मिल सकती है। पहाड़ और जंगल प्रकृति की ढाल हैं। इनके बिना घाटी बाढ़ और भूस्खलन की स्थायी चपेट में आ जाएगी, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी।

भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने सही किया

» यूक्रेनी राष्ट्रपति जिलेसंकी ने अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के समर्थन में दिया बयान

» भारत ने कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, अमेरिका के दबाव और यूक्रेन की टिप्पणी के बीच संतुलन में भारत सरकार

स्वराज इंडिया न्यूज यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है। इसमें से आधा शुल्क रूस से तेल खरीदने को लेकर है। ट्रंप का कहना है कि भारत की इस खरीद से रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक मदद मिल रही है।

हालांकि, भारत ने साफ किया है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और वह किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है।

दुनियाभर के कई देश और अमेरिकी विशेषज्ञ इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा है कि रूस से लगातार तेल खरीद रहे देश पर शुल्क लगाना सही है। ज़ेलेन्स्की की यह टिप्पणी सीधे भारत-अमेरिका संबंधों के बीच आ खड़ी हुई है।रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद कर अपने नागरिकों और उद्योगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका और यूरोप रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत से दूरी बढ़ाने का जोखिम उठा रहे हैं। यूक्रेन की टिप्पणी इस तनाव को और गहरा कर सकती है, क्योंकि यह सीधे भारत के हितों को चुनौती देती है।

भारत सरकार युद्ध का समर्थक नहीं है, बल्कि शांति और स्थिरता का पक्षधर है। भारत ने बार-बार कहा है कि उसका रूस से व्यापार किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। यही कारण है कि भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए रूस से भी अपने गहरे संबंध जारी रखे हुए है।भारत के लिए सबसे अहम बात यह है कि वह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा कर रहा है। अमेरिका और यूक्रेन की आलोचना के बावजूद भारत ने यह संदेश दिया है कि उसके निर्णय केवल राष्ट्रीय हितों से तय होंगे, न कि किसी बाहरी दबाव से।